अदम गोंडवी की नज़्म व ग़ज़ल

हथियार उठा ले

गर खुदसरी की राह पर चलते हों रहनुमा।
कुर्सी के लिए गिरते संभलते हों रहनुमा।।
गिरगिट की तरह रंग बदलते हों रहनुमा।
टुकड़ों पे जमाखोर के पलते हों रहनुमा।।
जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले।

जब भुखमरी की धूप में जलते किसान हों।
मुंह में जुबान रखते हुए बेजुबान हों।।
नफ़रत की रूत में दंगों के शोले जवान हों।–
जम्हूरित के तन पे ज़िना के निशान हों।।
जनता को हक है हाथ में हथियार उठाले।

गर खुद को कोई मुल्क की तक़दीर समझ ले।
हर शै की अपने ख़्वाब की ताबीर समझ ले ।।
अपना बयान वेद की तहरीर समझ ले।
जनगण को ख़ानदान की जागीर समझ ले।।
जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले।

गांधी का मुल्क है मगर हालात हैं अजीबा।।
अफसर हैं घूसखोर वो जल्लाद हैं तबीब।
जनता को साफ पीने का पानी नहीं नसीब।।
रम पीके दुम हिलाते हैं फंनकार वो अदीब।
जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले।।

ग़ज़ल

1. नीलाम कर देंगे

जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे।
कमीशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे।।

सुरा व सुन्दरी के शौक में डूबे हुए रहबर।
दिल्ली को रंगीलेशाह का हम्माम कर देंगे।।

ये वंदेमातरम् का गीत गाते हैं सुबह उठकर।।
मगर बाज़ार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे।।

सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे।
अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे।।

2. वो औरत बतायेगी

वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है।
उसी के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है।।

इधर इक दिन की आमदनी का औसत है चवली का।
उधर लाखों में सेठों के तिजोरी की कमाई है।।
कोई भी सिरफिरा धमका के जब चाहे ज़िना कर ले।
हमारा मुल्क इस माने में बुधुआ की लुगाई है।।
रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बतायेगी।
जिसने जिस्म गिरवी रखके ये कीमत चुकाई है।।

पेज 1 का शेष भाग

डीसी की नाक तले लुटते ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले

आपराधिक कानून के अनुसार यह सीधे-सीधे धोखा-धड़ी एवं फ़र्जीवाड़े का मामला बनता है। उक्त सरकारी फ़ीस के अलावा जो पैसा फाइल कवर, डाक्टरी जांच, कम्प्यूटर आदि के नाम पर वसूला जाता है वह पूरी तरह डीसी व दोनों एसडीएम की निजी दुकानदारी है। इस दुकानदारी को चलाने के लिये रेडक्रास की आड़ ली जाती है। कहने को यह पैसा दान के रूप में ग़रीबों की भलाई के लिये वसूला जाता है। परन्तु ऐसा कुछ नहीं है। दान कभी भी जबरदस्ती नहीं वसूला जाता। जबरदस्ती तो सरकारी टैक्स वसूला जाता है जिसका हिसाब-किताब विधायिका व महालेखाकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या फ़िर ऐसी जबर्दस्ती गुंडों द्वारा की जाती है जो खुद ही वसूलते हैं, खुद ही खर्च करते हैं और खुद ही हिसाब देख लेते हैं। इसी रेडक्रास फंड से कभी गवर्नर रहे धनिक लाल मंडल के होटल (राजहंस) के बिल चुकाये जाते रहे तो कभी डीसी के घर का पूरा राशन-पानी का खर्चा। ज़िले में वीआईपी आगमन पर होने वाले तमाम खर्चे भी यहीं से पूरे होते हैं। डीसी की पत्नी के लिये एक बढिया सी कार पेट्रोल व ड्राइवर का खर्चा भी इसी फंड से चलता है। हां दिखावे के लिये कभी कभार कुछ टुकड़े ग़रीबों को भी फेंक दिये जाते हैं। डॉक्टरी जांच का जहां तक सवाल है, रूल्स में स्पष्ट लिखा है कि यह किसी भी आरएमपी (पंजीकृत डॉक्टर) से कराई जा सकती है जो 10 से 15 रुपए में अथवा मुफ्त भी हो सकती है। किसी नियम में नहीं लिखा है कि एसडीएम कार्यालय में बैठा डॉक्टर ही इसके नाम पर मोटी फ़ीस वसूलेगा। वास्तव में फ़ीस के नाम की यह लूट उसकी तो कदापी नहीं होती, उसे तो वही 10-15 रुपए प्रति दस्तखत के ही मिलते हैं, बाकी लूट का माल तो अफ़सरों के पास पहुंच जाता है। मजेदार बात यह है कि हर वसूली की बकायदा रसीद कटती है, जिसे देखकर देने वाला आवेदक संतुष्ट रहता है। वह समझता है कि सब जायज व कानूनी वसूली हो रही है लेकिन अंत में आवेदक के पास कोई पर्ची या रसीद नहीं छोड़ी जाती, सारी पर्चियाँ आवेदन फ़ार्म के साथ फ़ाइल में लगाकर बाबू ले लेता है, बदले में एक पर्चा देता है जिसे दिखाकर एक या दो सप्ताह बाद लाइसैंस प्राप्त करता है।

बीके अस्पताल का एक्रेडेशन कराने के प्रयास में बाधक बनी सरकारी लूट

दरअसल जनता के पैसे से लाखों-करोड़ों की मशीनें खरीद डालना एक आसान काम है और उन्हें जनता की सेवा में लगाना बेहद कठिन काम है। ये दोनों काम दो अलग अलग वर्ग के लोग करते हैं, जिनके अपने अलग अलग हित हैं। खरीदने वाले वर्ग का हित मोटा कमीशन लेने से पूरा हो जाता है जबकि मशीनों को जनता की सेवा में लगाने वाले डॉक्टरों का हित मरीजों की सेवा से पूरा नहीं हो पाता।

इसके लिए एक तो उन्हें फालतू मेहनत करनी पड़ती है दूसरे वह कमीशन मारा जाता है जो उन्हें मरीजों को बाहर निजी अस्पतालों में भेजने पर मिलता है। इससे समझा जा सकता है कि संधू जैसी आयुक्त इस तरह के चाहे कितने ही दौरे कर लें, चाहे कितनी ही झाड-फटकार कर लें, कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है।

विदित है कि इसी शहर के चार बड़े निजी अस्पताल एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से किसी भी अस्पताल की लागत अथवा खर्चा बीके अस्पताल से ज़्यादा नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वे जनता को लूटते व ठगते तो जरूर हैं परन्तु अपने सिस्टम को नहीं लूटते। क्योंकि एक तो वे खुद सिस्टम के मालिक हैं, दूसरे सिस्टम ही यदि लुट-पिट जाएगा तो जनता उनके जाल में कैसे फ़ंसेगी?

दूसरी ओर सरकारी अस्पताल एवं पूरे स्वास्थ्य विभाग में हर स्तर पर जनता को लूटने के साथ-साथ सिस्टम को यथा-शक्ति बेच खाने में जुटे हैं, छोटे से लेकर उच्चाधिकारी एवं मंत्री तक।

जानकार बताते हैं कि बीके की पुरानी विंग वाली खंडहरनुमा इमारत पर गत 4 माह में करीब 2 करोड़ रुपए मरम्मत पर खर्च किए जा चुके हैं।

मरम्मत के इस काम को करने वाली एजेंसी और कोई नहीं एडीसी के मातहत चलने वाला एक विभाग है जिसका कार्यालय 15ए स्थित पुराने डीसी कार्यालय में है। जिले के जितने भी निर्माण संबंधी फ्रॉड कार्य होते हैं वे इसी विभाग के द्वारा किए जाते हैं। इस खंडहर में 2 करोड़ कहां लग गए किसी को नज़र नहीं आते। हर सरकारी लूट इसी तरह फाइलों में होती है। नज़र आने लगी तो जनता की नज़र न लग जाएगी!

चोर मोर के बीच तोड़ फोड़ की नूरा कुश्ती

भ्रष्टाचार, बेशर्मी, और बेहयायी का घिनौना नाटक

फ़रीदाबाद 10 मई के रोज़ एन आई टी नम्बर 5 के निरंकारी चौराहे पर लगभग 400 पुलिसकर्मी और इतने ही तमाशबीनों का जमावड़ा हमारे दिखावटी और जर्जर प्रजातान्त्रिक निज़ाम का भयंकर मजाक उड़ा रहा था। असल में नगर निगम का यह विशाल तोड़-कोड़ दस्ता, यहां पर चल रहे एक व्यस्त डिपार्टमेंटल स्टोर की पहली मंजिल पर हो रहे ग़ैर-कानूनी निमार्ण को तोड़ने के लिये पुलिस की भारी भरकम फ़ौज लेकर आया था। कुछ तथाकथित समाज सेवी और व्यापारी नेता भवन मालिक की गरीबी का हवाला दे कर इस कार्यवाही को रोकने की दुहाई दे रहे थे। जिस मुल्क में करोड़ों लोग 20 रुप्या रोज़ पर गुज़ारा करने के लिये मजबूर हों, जिस देश में सैकड़ों लोग रोज़ भूख की वजह से दम तोड़ते हों, वहां पर लाखों रुप्या महीना किराया वसूलने वाले मार्किट मालिक को ग़रीब बताना देश के गरीबों के मूंह पर थूकने जैसा अपराध है।

असल में जब इस बिल्डिंग का पहला तल बना था, यह निगम अधिकारी तब भी आये थे। हथौड़ा तब भी चला था परन्तु हमेशा की तरह कुछ दलालों, नेताओं समाजसेवियों ने बिचोलिया बन कर सौदा पटा दिया। सब ने बाकायदा अपना हिस्सा लिया और भवन बन कर तैयार हो गया। कई सालों से यहां पर एक डिपार्टमैन्टल स्टोर धड़ल्ले से चल रहा है। समय के साथ-साथ भवन मालिक की ज़रूरतें और ख्वाबों ने उड़ान भरी तो उस ने पहली सुनिश्चित मंजिल का निर्माण करने की योजना बनाई। सब कुछ ढंग से हुआ और भवन की पहली मंज़िल का लैन्टर बिना किसी रुकावट के डाल दिया गया। बहती गंगा में सभी ने खुल कर स्नान किया। इसी बीच उच्च न्यायालय की एक जन हित याचिका ने अकूत सम्पत्ति अर्जित करने वाले निगम अधिकारियों को हरकत में आने के लिये मजबूर किया। सच तो यह है शहर की मुख्य सड़कों पर बनी 90 प्रतिशत इमारतें नगर निगम द्वारा तय किये गये खोखले आधारहीन नियमों पर खडा नहीं उतरती हैं ऐसे में 400 पुलिस कर्मियों को ले कर10 मई 2013 को पांच नम्बर में सिर्फ़ पांच जगह पर ही यह दिखावटी तोड़-फ़ोड़ क्यों की गई।

छान-बीन करने पर जो जवाब आया वो यह है कि करोड़ों रु. के इस धन्धे में ईमानदारी से रिश्वत न पहुंचाने के जुर्म की हल्की सी सज़ा है यह कार्यवाही। पांच नम्बर सी बलाक में एक बिल्डर द्वारा लगभग 34 दुकानों का निर्माण किया गया। इस बहुमंजिला इमारत के कई लैन्टर दिन की खुली रौशनी में डाले गये।

बजाए पूरी तयशुदा रकम पहुंचाने के एक भूतपूर्व मंत्री और स्थानीय भूतपूर्व पार्षद का बड़ा सा बैनर निर्माण स्थल पर लगा कर, नासमझ बिल्डर ने अपनी शक्ति का ऐलान किया। जैसा कि ज़ाहिर है इस शक्तिप्रदर्शन ने काम नहीं किया और सरकारी दामाद दल-बल के साथ आ कर चेतावनी दे गये।

गौरतलब बात यह है कि चार सौ लोगों की सुरक्षा फौज़ लेकर निगम कर्मचारियों ने अपने तजुर्बे और दूरदशिर्ता का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ दो चार जगह पर बीस-बीस हथौड़े मारे जिन्हें रिपेयर करने में ज़रा भी असुविधा नहीं होगी। हां इन सुराखो और हथौड़े-बाजी की फ़ोटोग्राफ़ीं करके उच्चन्यायालय की आंखों में धूल झोकने के लिये पर्याप्त सामग्री इकट्ठी कर ली गई है।

काबिले- ग़ौर बात यह भी है कि इस मौके पर स्थानीय पार्षद परिवार की अनुपस्थिति भी गरमागरम चर्चा का विषय है। लोगों का कहना है कि यदि पार्षद या सामाजिक कार्यकर्ता बजाए इस काले धंधे में शामिल होने के लोगों को नियमों का पालन करने या निगम के सदन में भवन निर्माण के लिये रखी गई अर्नगल और अतर्किक शर्तों को बदलने के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करे तो ऐसी शर्मनाक स्थितियां पैदा ही नही हो।

नगर के एक भूतपूर्व विधायक राजनैतिक राटियां सेकने की मुराद से अपने चंद चमचों के साथ रोज़ कहीं न कहीं तोड़-फोड़ कार्यवाही के ख़िलाफ़ भाषणबाजी करते दिखाई देते हैं पर लोगों का कहना है कि पांच नम्बर डी ब्लाक में नगर निगम अधिकारियों ने उपरोक्त पूर्व विधायक के सगे साले की निर्माणाधीन दुकानों पर हथौड़ा चलाने का दुस्साहस किया है जिससे विधायक महोदय की प्रतिष्ठा और जेब दोनों को भारी झटका लगा है।

पांच नम्बर डी ब्लाक में एक प्रापर्टी डीलर की इमारत पर हथौड़ा चलाते वक्त उमड़ी भीड़ में लोग पूछ रहे थे कि ये निगम वालें, लोगों के लाखों करोड़ों रू. भवनों पर खर्च हो जाने के बाद ही क्यो जागतें है।

अभी तक प्राप्त सुचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान निगम कमिश्नर डॉक्टर अभय सिंह यादव का दामन इस अवैध निर्माण माफिया के छीटों की ज़द से बाहर है। यदि निगम कमिश्नर इस अनैतिक बंदर-बांट में शामिल नहीं तो बिना एक पल की देरी किए उन कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरियां क्यों नही समाप्त कर दी जाती जिनके कार्यकाल और क्षेत्रों में एक लम्बे अर्से से गैर-कानूनी निमाण बेखौफ़ होता रहा।